रजिस्टर्ड नं० एल०-33-एस० एम० 13-14/98

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 जनवरी, 1998/13 पौष, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(ख-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 दिसम्बर, 1997

संख्या जी० ए० बी०-I ए (ए) 8/85.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में वर्तमान तहसील अम्ब से 10 पटवार वृतों नामतः गिन्डपुर, खरोह, भटेहड़, धर्मशाल महन्ता, वधमाना, छपरोह, डूहल भटवालां, डूहल बगवालां, लोहारा-I और लौहारा-II के क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुए उप-मण्डल अम्ब के अधीन हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में उप-तहसील भरवाईं नाम से ज्ञात एक नई उप-तहसील का सृजन किया जाए, जिसका मुख्यालय भरवाईं होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित 10 पटवार वृतों, जिन्हें जिला ऊना की विद्यमान तहसील अम्ब से अपवर्जित किया गया था,

3159-राजपत्र/97-3-1-98—1,275. मूल्य : 1 रुपया।

को सम्मिलित करते हुए जिला ऊना के अम्ब उप-मण्डल (नागरिक) में एक नई उप-तहसील भरवाई का तुरन्त प्रभाव में सृजन करती है, जिसका मुख्यालय भरवाई होगा, अर्थात् :—

क्रमांक	उप-मण्डल (नागरिक) का नाम	उप-तहसील का नाम	पटवार वृतों का नाम
1.	अम्ब	भरवाई	1. गिन्डपुर 2. खरोह 3. भटेहड़ 4. धर्मसाल महन्ता 5. वधमाना 6. छपरोह 7. डूहल भटवालां 8. डूहल बगवालां 9. लोहारा-I 10. लोहारा-II

आदेश द्वारा,

ए० एन० विद्यार्थी,
मुख्य सचिव ।

[Authoritative english text of this Government Notification No. GAB-1A(1)8/85, dated 18-12-97 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(B-Section)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 18th December, 1997

No. GAB-1A (A)8/85.—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary so to do that a new Sub-Tehsil to be known as Sub-Tehsil Bharwain in District Una of Himachal Pradesh with headquarter at Bharwain under Sub-Division (Civil) Amb in District Una, Himachal Pradesh may be created by excluding the area of 10 Patwar Circles namely Gindpur, Kharoh, Bhated, Dharamsal Mahanta, Vadhmana, Chhaproh, Duhal Bhatwalan, Duhal Bhagwalan, Lohara-I and Lohara-II from the present Tehsil Amb.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Bharwain by including following 10 Patwar Circles so excluded from the existing

Tehsil Amb in District Una with headquarter at Bharwain in Amb Sub-Division (Civil), District Una with immediate effect, namely :—

Sl. No.	Name of Sub-Division (Civil)	Name of Sub-Tehsil	Name of Patwar Circles
1.	Amb	Bharwain	1. Gindpur 2. Kharoh 3. Bhated 4. Dharamsal Mahanta 5. Vadhmana 6. Chhaproh 7. Duhal Bhatwalan 8. Duhal Bagwalan 9. Lohara-I 10. Lohara-II

By order,

A. N. VIDYARTHI,
Chief Secretary.

भाषा एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 दिसम्बर, 1997

संख्या एल0 सी0 डी0-ई(4)5/96.—राज्य सरकार की यह राय है कि "दुर्वेश्वर महादेव मन्दिर तथा भागसू नाग मन्दिर" स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा के और अच्छे प्रशासन और इससे सम्बन्धित सम्पत्ति के संरक्षण और परिरक्षण के लिए लोकहित में पग उठाये जाने समीचीन और आवश्यक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का 18) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में विद्यमान क्रम संख्या 20 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या 21 जोड़ते हैं, अर्थात् :—

क्रम संख्या 21 : दुर्वेश्वर महादेव मन्दिर तथा भागसू नाग मन्दिर, जिला कांगड़ा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authorised English Text of this Department Notification No. LCD-E*(4)5/96, *dated* 12-12-1997 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

LANGUAGE AND CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th December, 1997

No. LCD-E(4)5/96.—Whereas the State Government is of opinion that it is expedient and necessary in the public interest to take steps for the better administration and for

the protection and preservation of properties appurtenant to "Durveshwer Mahadev Temple and Bhagsu Nag Temple" at Dharamshala, District Kangra.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (I) of Section 29 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add after the existing Sl. No. 20 of the Schedule-I of the aforesaid Act, the following Sl. No. 21, namely :—

Sl. No. 21: Durveshwer Mahadev Temple and Bhagsu Nag Temple, District Kangra.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

ANNEXURE 'A'

SCHEDULE-I

[*See* Section 1 (3) and Section 29]

Sl. No. 1	Name of Hindu Public Religious Institutions or Charitable Endowment 2
1.	Tara Devi Temple at Tara Devi, District Shimla.
2.	Durga Mata Temple at Hatkoti, District Shimla.
3.	Bhima Kali Ji Temple, Shri Raghunath Ji, Shri Nar Singh Ji, Shri Lankda Devta Ji Located at Sarahan, District Shimla.
4.	Hanuman Temple at Jakhoo, Shimla, District Shimla.
5.	Shri Naina Devi Temple, Naina Devi.
6	Jawalamukhi Temple at Jawalamukhi, District Kangra.
7.	Brajeshwari Devi Temple at Kangra, District Kangra.
8.	Chintpurni Temple at Chintpurni, District Una.
9.	Mandir Damtal at Damtal, District Kangra.
10.	Temple Baba Balaknath of Deotsidh, District Hamirpur.
11.	Ajodhya Nath Temple at
12.	Dattatreya Temple at Dutt Nagar, Shimla.
13.	Shri Durga Temple Sharai Koti Rampur Bushehar, Shimla.
14.	Shri Badri Vishal Via Atterian and Nar Singh Dev Temple, Nagrota Surian, Kangra.
15.	Shri Laxmi Narayan Mandir, Chamba.
16.	Temple Thakur Dwara Bai Ji Sahiba Paonta, District Sirmaur.

1	2
17.	Shri Shahtalai Group of Temples: (i) Main Mandir Baba Balak Nath, Shahtalai. (ii) Second Temple Baba Balak Nath Shahtalai. (iii) Temple Vat Vriksh Shahtalai. (iv) Temple Gurna Jhari Shahtalai.
18.	Shri Ashta Bhuja Math Temple, Bohan near Jawalamukhi, Tehsil Dehra Gopipur, District Kangra.
19.	Chamunda Nandikeshwar Mandir, District Kangra.
20.	Gorakh Dibbi Mandir District Kangra.
21.	Dalveshwer Mahadev Temple and Bhagsu Nag Temple at Dharamshala, District Kangra.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 अक्तूबर, 1997

संख्या रैव-डी (जी) 6-33/86-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) की धारा 13 और हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का 19) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993, जिनका पूर्व प्रकाशन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 11 जून, 1997 द्वारा राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 23 जून, 1997 में हो चुका है, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1997 है।

2. नियम 4, 6 और 8 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के खण्ड (iii), नियम 6 के खण्ड (7) और नियम 8 के उप-नियम (1) की मद (x) में "भूतपूर्व सैनिकों, शब्दों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, स्वतन्त्रता सेनानियों", शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

3. नियम 7 का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों के नियम 7 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"7 पट्टे की मंजूरी.—इन नियमों के अधीन पट्टे, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) और (3) में की सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, स्तम्भ (1) में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा मंजूर किए जाएंगे :—

सारणी

मंजूरी प्राधिकारी 1	क्षेत्र तक 2	अनधिक अवधि के लिए 3
1. कलैक्टर	$1\frac{1}{2}$ बीघा तक	10 वर्ष
2. मण्डलायुक्त	$2\frac{1}{2}$ बीघा तक	20 वर्ष
3. वित्तायुक्त	5 बीघा तक	50 वर्ष
4. राज्य सरकार	20 बीघा तक	99 वर्ष

परन्तु राज्य सरकार, लोक हित में लोक प्रयोजन के लिए 20 बीघा से अधिक क्षेत्र का पट्टा प्रदान कर सकेगी ।

4. नियम 10 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 10 में शब्दों प्ररूप अ "के पश्चात (नवीनतम जमाबन्दी, ततीमा, विक्रय मूल्य की पांच साला औसत और प्रस्तावित भूमि की नवीनतम बाजारी कीमत)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

5. नियम 13 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 13 में :—

(i) उप-नियम (1) में दूसरी बार आये "कुलैक्टर" शब्द के लिए "कुलैक्टर जहां वह मंजूरी प्राधिकारी नहीं है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उप-नियम (2) में दूसरी बार आए शब्दों "उप मण्डलाधिकारी (सिविल) के माध्यम से" के पश्चात "और जहां क्षेत्र 2½ बीघा से अधिक बढ़ जाता है मण्डलायुक्त के माध्यम से" अंत: स्थापित किए जाएंगे ।

(iii) उप-नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात: —

"(3) जहां कुलैक्टर मंजूरी प्राधिकारी है, कलैक्टर पट्टा मंजूर करने से पूर्व, पर जहां कलैक्टर मंजूरी करने मे मंजूरी प्राधिकारी नहीं हैं तो मंजूरी प्राधिकारी, उप-नियम (2) के अधीन प्राप्त कलैक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने से पूर्व भूमि का पट्टा प्रदान किए जाने का न्यायोचित्य और उपयुक्तता के सम्बन्ध में सरकार के उस विभाग जिससे आवेदक, संस्थान या निगमित निकाय होने या रजिस्ट्रीकृत है, या मान्यता प्राप्त है, या इसके क्रियाकलापों से सहबद्ध है, के विचार अभी-निश्चित करे ।।"

6. नियम 20 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 20 में, "पट्टे को रद्द कर सकेगा, और", "शब्दों और चिन्ह के लिए" उसके द्वारा, मंजूर पट्टों को रद्द कर सकेगा और अन्य मामलों में शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

7. नियम 26 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 26 में, शब्द और चिन्ह "कलैक्टर", के पश्चात, "मण्डलायुक्त", शब्द और चिन्ह अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

8. नियम 27 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 27 में पहले आए शब्द और चिन्ह "कलैक्टर" के पश्चात शब्द "मण्डलायुक्त" अन्त:स्थापित किया जाएगा और दूसरी बार आए शब्दों "कलैक्टर" के बाद चिन्ह "," और शब्द "मण्डलायुक्त" अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

आदेश द्वारा,

हर्ष गुप्ता,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[Authoritative English Text of Government Notification No. Rev. D (G) 6-33/86-III, dated 27-10-1997 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th October, 1997

No. Rev. D (G) 6-33/86-III.—In exercise of the powers vested in him under section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act 18 of 1974) and section 26 of the Himachal Pradesh Ceilling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 1993, the same having been previously published in the Rajpatra (Extraordinary), Himachal Pradesh, dated 23rd June, 1997 *vide* this Department Notification of even number dated 11th June, 1997, namely:—

1. *Short title,*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Second Amendment) Rules, 1997.

2. *Amendment of rules* 4, 6 *and* 8.—In clause (*iii*) of rule 4, clause (7) of rule 6 and item (x) of sub-rule (1) of rule 8 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 1993 (hereinafter called the said rules) for the words "ex-servicemen" the words "Ex-servicemen, war widows, freedom fighters" shall be substituted.

3. *Substitution of rule* 7.—For rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"7 Sanction of lease.—The leases under these rules shall be sanctioned by the authorities mentioned in column (1) subject to limits given in column (2) and (3) in the table below:—

TABLE

Sanctioning authority 1	Up to the area 2	for the period not exceeding 3
1. Collector	upto 1½ bighas	10 years
2. Divisional Commissioner	upto 2½ bighas	20 years
3. Financial Commissioner	upto 5 bighas	50 years
4 State Government	upto 20 bighas	99 years:

Provided that the State Government may grant the lease of an area exceeding 20 bighas for public purposes in the public interest."

4. *Amendment of rule* 10.—In rule 10 of the said rules, after the words "Form-A" the words and brackets "(alongwith copy of latest jamabandi, tatima, five years average sale price and latest market value of proposed land)", shall be inserted.

5. *Amendment of rule* 13.—In rule 13 of the said rules.—

(*i*) in sub-rule (1), for the words "then the Collector", the words "then the Collector, where he is not the sanctioning authority" shall be substituted.

(*ii*) in sub-rule (2), after the words "through Sub-Divisional Officer (Civil)", occuring for the second time, the words "and where the area exceeds 2½ bighas through the Divisional Commissioner" shall be inserted.

(*iii*) after sub-rule (2) the following new sub-rule (3) shall be added, namely:—

"(3) Where the Collector is the sanctioning authority, the Collector before sanctioning the lease, or where Collector is not, the sanctioning authority, the sanctioning authority before considering the report of the Collector, received under sub-rule (2), shall in relation to the justification and appropriateness for the grant of lease of land, ascertain the views of the Department of Government with which the applicant, being an Institution or a Corporate body, is either registered or recognised, or is co-related into activities."

6. *Amendment of rule* 20.—In rule 20 of the said rules, for the words and sign "cancel the lease, and," the words "cancel the lease sanctioned by him and in other case," shall be substituted.

7. *Amendment of rule* 26.—In rule 26 of the said rules after the word and sign "Collector," the words and sign, "Divisional Commissioner", shall be inserted.

8. *Amendment of rule* 27.—In rules 27 of the said rules, after the word and sign, "Collector," occurring for the first time, the words, "Divisional Commissioner" shall be inserted and after the words "Collector" occurring for the second time, the sign "," and words "Divisional Commissioner" shall be inserted.

By order,

HARSH GUPTA,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 नवम्बर, 1997

संख्या टी0 सी0 पी0-एफ0(6)-2-2/97.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग ऐक्ट, 1977 (1997 का 12 की धारा 13 की उप-धारा 2 के खण्ड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा घोषित करती है कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या पी0 वी0 डब्ल्यू (बी) 26 (31)/86, तारीख 30-6-1986 द्वारा अधिसूचित सराहन योजना क्षेत्र, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, का गठन करने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र तुरन्त प्रभाव से योजना क्षेत्र नहीं रहेगा।

आदेश द्वारा,

हस्ता/-
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of the Department Notification No TCP-F*(6)-2-2/97, *dated* 28-11-1997 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th November, 1997

No. TCP-F (6)-2-2/97.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare that whole of the area constituting Sarahan Planning Area, District Sirmaur, Himachal Pradesh notified *vide* Public Works Department Notification No. PBW(B&R) (B) 26(31)/86, dated 30-6-1986 shall cease to be a planning area with immediate effect.

By order,

Sd/-
Financial Commissioner-cum-Secretary.

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 1997

संख्या टी० सी० पी०-एफ० (5)-6/96.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग ऐक्ट, 1977 (1977 का 12) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित राजस्व गांवों (हदबस्त संख्या) को चम्बा योजना क्षेत्र, जोकि अधिसूचना संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी० एण्ड आर०) (बी०) 26 (32)/86, तारीख 5 जुलाई, 1986 द्वारा गठित किया गया है, से अपवर्जित करती है, अर्थात् :—

क्र० सं० 1	योजना क्षेत्र से अपवर्जित किए गए राजस्व गांवों का नाम 2	हदबस्त संख्या 3
1.	मुंगला	174
2.	उदयपुर	16
3.	सुरां	236

उपरोक्त गांवों के अपवर्जन के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल नीचे दिए गए विनिर्देश के अनुसार, चम्बा योजना क्षेत्र की परिसीमाओं को पुनः परिभाषित करती है :—

उत्तर .—हरिपुर हदबस्त नं० 283 की उत्तरी सीमा तक।

पूर्व .—हरिपुर हदबस्त नं० 283, सरोल हदबस्त नं० 282, चम्बा हदबस्त नं० 176, मुंगला हदबस्त नं० 175 और करियां हदबस्त नं० 174 की पूर्वी सीमा तक।

दक्षिण .—करियां हदबस्त नं० 174 की दक्षिण सीमा तक।

पश्चिम :—सुल्तानपुर हदबस्त नं0 18, चम्बा हदबस्त नं0 176, मुंगला हदबस्त नं0 175 एवं करियां हदबस्त नं0 174 की पश्चिमी सीमा तक जो रावी नदी के साथ-साथ लगती है ।

चम्बा योजना क्षेत्र के अन्तर्गत अब निम्नलिखित पूर्ण राजस्व होंगे :—

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	राजस्व हदबस्त संख्या
1	2	3
1.	चम्बा	176
2.	मुंगला	175
3.	करियां	174
4.	सुल्तानपुर	18
5.	हरिपुर	283
6.	सरोल	282

आदेश द्वारा,

ओ0 पी0 यादव,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department notification No. TCP-F* (5)-6/96, *dated* 11*th December*, 1997 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 11*th December*, 1997

No. TCP-F-(5)-6/96.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 13 of H.P. Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exclude the following revenue villages (Hadbast Nos., from Chamba Planning Area constituted *vide* Notification No. PBW (B&R) (B) 26 (32)/86, dated 5th July, 1986, namely :—

Sl. No.	Name of Revenue villages excluded	Hadbast No.
1.	Mungala	174
2.	Udaipur	16
3.	Suri	236

Consequent upon the exclusion above villages, the Governor of H. P. is pleased to redefine the limits of the Chamba Planning area as per specification given below :—

North. Upto North boundary of Hadbast No. 283 of Haripur.

East .—Upto the Eastern boundary of Haripur Hadbast No. 283, Sarol Hadbat No. 282, Chamba Hadbast No. 176, Mungala Hadbast No. 175 and Kariyan Hadbast No. 174.

South .—Upto the South boundary of Kariyan Hadbast No. 174.

West .—Upto the Western boundary of Sultanpur Hadbast No. 18, Chamba Hadbast No. 176, Mungala Hadbast No. 175 and Kariyan Hadbast No. 174 falling along river Ravi.

Following complete revenue Hadbast will be in the Chamba Planning Area now :—

Sl. No.	Name of Area	Revenue Hadbast No.
1.	Chamba	176
2.	Mungala	175
3.	Kariyan	174
4.	Sultanpur	18
5.	Haripur	283
6.	Sarol	282

By order.

O. P. YADAVA,
Financial Commissioner-cum Secretary.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 दिसम्बर, 1997

संख्या एल0 एस0 जी0-ए0 (4)-4/95.—हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 35 और धारा 36 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 395 के खण्ड (6) भाग 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम शिमला द्वारा बनाई गई, और राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित/पुष्ट निम्न उप-विधियों में संशोधन, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 397 (1) के अधीन अपेक्षित है, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह उप-विधियां, शिमला नगर निगम की सीमाओं में भीतर राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगी, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम शिमला नगर निगम (महापौर, उप-महापौर और पार्षदों के लिए सुविधाएं) (संशोधन) उप-विधियां, 1997 है ।

2. नियम 8 का संशोधन.—विद्यमान नियम 8, को उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा ।

इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम (2) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(2) पार्षद अपने प्राईवेट टेलीफोन से, यदि कोई हो, हर महीने दिनांक 17-10-1997 से निशुल्क 600 काल करने के हकदार होंगे, और इस के व्यय को उन्हें नगर निगम, शिमला द्वारा प्रति-पूर्ति की जाएगी।

आदेश द्वारा,

रवि ढोगरा,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English Text of Government Notification No. LSG-A* (4) 4/95, *dated* 16-12-1997 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th December, 1997

No. LSG-A (4) 4/95. —The following amendments of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Facilities to the Mayor, Deputy Mayor and Councillors) Bye Laws, 1996, made by the Municipal Corporation Shimla in exercise of the powers conferred upon it under clause (6) of Part I of Section 395 read with Section 35 and sub-section (3) of Section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) having been confirmed by the Governor of Himachal Pradesh as required under Section 397 (1) of the aforesaid Act are hereby published for general information. They shall come into force within the limits of Municipal Corporation Shimla from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), namely :—

1. *Short title.* These bye-laws may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Facilities to the Mayor, Deputy Mayor and Councillors) (Ammendment) Bye-Laws, 1997.

2. *Amendment of Rule* 8.—The existing rule 8, may be numbered as sub-rule (1) so numbered, the following sub-rule (2) shall be inserted, namely :—

(2) The Councillors shall be entitled upto six hundred free calls per month from their private telephone number, if any *w.e.f.* 17-10-1997 expenditure of which would be re-imbursed by the Muncipal Corporation, Shimla.

By order,

RAVI DHINGRA,
F. C.-cum-Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।